

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

<b>प्रार्थीया</b> वसुन्धरा पुत्री स्व. मुरलीधर पत्नी कमल किशोर जाति ब्राह्मण निवासी खजुर वाली कोठी, श्रवणपुरा हाल निवासी दुर्गा कॉलोनी, रामपुरा रोड़ सीकर	<b>ब ना म</b>	<b>अप्रार्थीगण</b> गीतादेवी पत्नी स्व. मुरलीधर जाति ब्राह्मण निवासी खजुर वाली कोठी श्रवणपुरा वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र = बाबत रिसीवर नियुक्त करने अन्तर्गत धारा 212(2) R.T.Act 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.		
<b>प्रार्थना-पत्र नम्बर</b> 868/2021		<b>GCMS No.</b> 2021/1170
<b>तारीख हुक्म</b>	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
22.12.2021	<p>                     वकील प्रार्थी द्वारा यह राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत बाबत रिसीवर नियुक्त करने अन्तर्गत धारा 212(2) R.T.Act 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत एवं प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अप्रार्थीगण विरुद्ध प्रस्तुत किये। प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण सं. 791/2021 वसुन्धरा बनाम गीतादेवी में ग्राम श्रवणपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 345, 346, 347 के रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2021 को प्रदान किये गये। स्थगन जारी होने के उपरान्त दिनांक 29.11.2021 को नामान्तकरण संख्या 292 अप्रार्थी संख्या 11 से 15 के पक्ष में विक्रय पत्र जो कि बक्शीशनामा के आधार पर किया गया था के आधार पर तहसीलदार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया।                 </p> <p>                     स्थगन आदेश जारी होने के उपरान्त भी अवैध हस्तान्तरणों की आड़ में अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण करने पर उतारू है, वादग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति है अप्रार्थीगण प्रार्थीया को अवैध हस्तान्तरणों की आड़ में बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी, जिसकी पूर्ति होना असंभव होगा। जटिलताएँ उत्पन्न हो जायेगी, न्यायालय व पक्षकारों का समय व धन बर्बाद होगा, वादग्रस्त आराजीयात हिन्दू संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का हक हिस्सा बाई बर्थ है, इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रमाणित है, प्रार्थीया अपने पैतृक भूमि की रक्षा करने के लिए यह प्रार्थना-पत्र न्यायालय में पेश करना लाजमी हो गया है। अतः विवादित आराजी पर रिसीवर नियुक्त कर भूमि रिसीवर के कब्जे में दिये जाने के आदेश फरमावें।                 </p> <p>                     वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रापक (रिविसर) की नियुक्ति के लिये माननीय उच्चतम न्यायालय जुगल किशोर बनाम मांगीलाल 1976                 </p>	



वी.ला.नो.64 माधोपुरी बनाम बंशीधर 1985 वी.ला.नो. 189, जीतासिंह बनाम राज. राज्य आर.आर.डी. 214 फकीर शाह बनाम राज. राज्य 1994 आर.आर.डी. 40 के अनुसार पांच सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं :-

- 1- एक वाद के लम्बित रहते प्रापक की नियुक्ति न्यायालय के विवेकाधिकार पर आश्रित है।
- 2- न्यायालय को वादी द्वारा यह सबूत देने पर कि वाद में उसके सफल होने का प्रथम दृष्टया अति उत्तम अवसर है इसके लिए सिवाय प्रापक नियुक्त नहीं करना चाहिये।
- 3- वादी केवल यही दर्शित नहीं करे कि सम्पत्ति के लिये प्रतिकूल और विवादास्पद दावे हैं, परन्तु वह कोई आपत्ति या खतरा या हानि भी दर्शित करे जो तुरन्त कार्यवाही की मांग करती हो, और उसको अपने अधिकार के बारे में वह युक्तियुक्त रूप से स्पष्ट और संदेह से परे हो। खतरे (भय) का तत्व विचार करने के लिये महत्वपूर्ण है।
- 4- प्रापक वहाँ नियुक्त नहीं किया जावेगा, जब उसका प्रभाव "वास्तविक" (de-facto) कब्जे से प्रतिवादी को वंचित करना (हटाना) होता हो। क्योंकि कि वह अपूर्ण्य दोष कारित कर सकता है। यह भिन्न होगा जहाँ संपत्ति अधर झूल (in medio) दर्शित हो। अर्थात् किसी के उपभोग में नहीं हो।
- 5- न्यायालय प्रापक नियुक्त करने के आवेदन पर आवेदन करने वाले पक्षकार के आचरण को देखता है और साधारणतया हस्तक्षेप करने से मना कर देगा। जब तक कि उसका आचरण कलंक से मुक्त न हो जाये।

आलोच्य प्रकरण के मूल वाद की विषय वस्तु खसरा नम्बर 345, 346, 347 किस्म क्रमशः गै.मु.कुआ, गै.मु.आबादी व चाही है मूल विवाद पैतृक कृषि भूमि के सम्बन्ध में है राजस्व अभिलेख से स्पष्ट परिलक्षित है कि दर्ज खातेदार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अजनबी भिन्न व्यक्ति प्रतिवादी सं. 11 ता 15 को वाद में विचाराधीन भूमि का विक्रय कर दिया एवं उसका नामान्तरकरण सं. 292 दिनांक 29.11.2021 को क्रेतागण अप्रार्थी संख्या 11 से 15 के पक्ष में कर दिया जबकि दिनांक 29.11.2021 को इस न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावशील था।

आलोच्य प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य तो पूर्ण रूप से परिलक्षित हो रहा है कि मूल वाद की विषय वस्तु खतरे या हानि में हो रही है, वाद में उल्लेखित सजरा खानदान के उत्तराधिकारीगण के अन्य भिन्न अजनबी व्यक्ति को हस्तान्तरण किये जाने पर मूल वाद की विषय वस्तु को खुर्द-बुर्द किये जाने की प्रबल संभावता है, यदि मूल वाद की विषय वस्तु ही खुर्द-बुर्द हो गई तो वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष का उद्देश्य समाप्त प्रायः हो जावेगा एवं वाद बहुलता बढ़ेगी।

उक्त प्रकरण के सभी तथ्यों पर मनन करने पर विधि द्वारा न्यायालय को प्रदत्त विवेकाधिकार का उपयोग करते हुये आदेश दिया जाता है कि मूल वाद में विचाराधीन ग्राम श्रवणपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 345, 346, 347 में से गै.मु.कुआ व गै.मु.आबादी जो क्रमशः पेयजल सुवधि एवं रहवासीय



*(Handwritten signature)*

मु.न. ६४/२०२१

१ जुलै १, २०२१

उपयोग में आ रहा हो को छोड़ने हुये शेष भूमि खसरा नम्बर 347 रकबा 3.98 को कुर्क कर तहसीलदार कुचामनसिटी को रिसिवर (प्रापक) नियुक्त किया जाता है। आदेश की पालना में रिसिवर तहसीलदार कुचामनसिटी उक्त विवादित आराजी को अपने कब्जे में लेकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 22-12-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



22/12/21

(बाबुलाल ७१२)  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी (नागौर)